# भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

## दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

**आदरणीय कॉमरेडों, मित्रों, लाल सलाम्!**

### दक्षिण बस्तर में ड्रोन हमलों की घोर निंदा करें!

### बस्तर की जनता पर थोपे गए युद्ध के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें!

### सच्चाई को जानिए, सामने आइए!

१. दंडकारण्य के दक्षिण बस्तर के मेट्टागुडेम, बोट्टेम, साकिलेर, मडपा दुलेड, कन्नेमरका, पोट्टेमंगुम, बोत्तम, रासम, एर्राम गांवों के जंगलों में विशेष रूप से 4 जगहों पर रात 1 बजकर 9 मिनट से 1 बजकर 40 मिनट तक हमारी पीएलजीए एवं जनता को निशाना बनाकर 50 से अधिक ड्रोनों द्वारा 50 से अधिक शक्तिशाली बम (हाई एक्सप्लोजिव बम) गिराए गए.

२. इन हमलों की चपेट में आदिवासियों की वो झोपड़ियां भी आयीं जिन्हें महुआ, टोरा आदि वनोपज रखने के लिए बनाया जाता है. वहां ग्रामीण भी सोते हैं.

३. सतर्कता व सावधानियां बरतने के कारण हालांकि इस बार के इन हमलों में हमारी पीएलजीए, जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है.

४. पिछले साल 19 अप्रैल को भी बोत्तालंका के जंगलों में 12 बमगिराए गए थे जिसकी रिपोर्टिंग पत्रकारों ने की थी. हमने सबूत के तौर गिराए गए ड्रोनों को भी पेश किया था. आकाशीय बम धमाकों की आवाज सुनने वाली जनता ने अपने बयान दर्ज किए थे. पेड़ों व जमीन पर बमों से हुए नुकसानों के निशान दिखाए गए. जन सभाएं की गयी थीं. पुलिस अधिकारियों ने झूठ का सहारा लिया और हवाई बमबारी से इन्कार किया था. इस बार फिर एक बार पिछली बार से भी ज्यादा घातक व कई गुना अधिक बम गिराए गए थे. कई पत्रकारों ने ग्राउंड जीरो से बमबारी की असलियत की रिपोर्टिंग की. सच्चाई से रूबरू हुए. इतने बड़े ऑपरेशन जोकि मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक नुमा एअर स्ट्राइक्स हैं, को अंजाम देकर अभी बस्तर के आला पुलिस अधिकारी यह बोल रहे हैं कि उन्होंने हवाई बमबारी की ही नहीं है. यह सबसे बड़ा झूठ है. दरअसल भारत सरकार इस बदनामी से बचने के लिए कि वह अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध कर रही है, वह भी सेना और वायु सेना का उपयोग कर रही है, हवाई बमबारी कर रही है, झूठ बोल रही है.

५. इस बार के हमलों में स्थानीय पुलिस के अलावा, कोबरा, भारतीय सेना खासकर वायुसेना के जवान व अधिकारी, अत्याधुनिक ड्रोनों, हेलिकॉप्टरों के साथ वायु सेना के तकनीशियन, डीआरजी गुंडे, एसटीएफ और ग्रेहाउंड्स बल शामिल हैं.

६. इसकी तैयारी पिछले 50 दिनों से चल रही थी जो अब भी जारी है. रोज कई किस्म के ड्रोन उड़ते रहते हैं. यह असल में जनता पर युद्ध है जिसे अब भारतीय सेना लड़ रही है. परंतु पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पिछली बार की ही तरह इस बार की बमबारी को भी छुपा रहे हैं. वे इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं. वे झूठ बोल रहे हैं. उल्टे मावोआदी हिंसा की बातें ज्यादा प्रचार में लाते हैं. अभी हमारे संघर्ष इलाकों के सभी कैंपों में छद्म वेष में भारतीय सेना के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं. हवाई बमबारी पामेड, विंपा, चेन्नापुरम तीनों जगह से समन्वित ढंग से संचालित की गयी. अगले हमले की भारी तैयारियां अभी भी पामेड में जारी हैं. कैंप को हरे रंग के अपारदर्शी कपड़े से ढक कर कार्ययोजना पर आला अधिकारियों की देखरेख में अमल हो रहा है.

७. इन हमलों को प्रधान मंत्री के इशारे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अजित दोभाल, विजय कुमार के निर्देशन में, भूपेश बघेल की सहमति से पुलिस, अर्धसैनिक व सैन्य बलों व उनके अधिकारियों की प्रत्यक्ष देखरेख में अंजाम दिया गया था. वायु सैनिक अधिकारी, तकनीशियन प्रमुख रूप से शामिल हैं. अभी के हमलों के लिए 5–6 हजार फोर्स को तैनात किया गया है. चेरला, पामेड, बासागुडा से लेकर सभी कैंपों – कोलाय, कडियुम, पोट्टोंग, विंपा, एल्मागुंडा, सोनाड एरवु, बुरकापाल, चिंतलनार, चिंतागुफा, बासागुडा, चेन्ना पुरम में ये फोर्स तैनात है.

८. हाल ही में २१ अप्रैल को पूसगुप्पा जहां पिछले कई महीनों से स्थानीय मूलवासी जनता प्रस्तावित कैंप के विरोध में धरनारत हैं, उनकी मनोभावनाओं को रौंदते हुए, बिना ग्रामसभा की सहमति के कैंप बैठाया गया. साथ ही उसी दिन उल्द्रिपेंटा में एक और कैंप लगाया गया. बस्तर में पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून लागू हैं. ग्रामसभाओं की सहमति के बिना लगाए गए एवं प्रस्तावित कैंपों व नरसंहारों के खिलाफ बस्तर के कई जगहों पर मूलवासी जनता नवंबर, २०१९ से आंदोलनरत है. इन आंदोलनों की धज्जियां उड़ाते हुए नए-नए कैंप लगाए जा रहे हैं, झूठी मुठभेड़ हत्याएं की जा रही हैं, अवैध गिरफ्तारियां, बेदम पिटाई, महिलाओं पर अत्याचार बेरोकटोक जारी हैं.

९. यह युद्ध भारत सरकार दरअसल यहां के जल–जंगल–जमीन एवं संसाधनों को हड़पने, उन्हें देशी, विदेशी बड़े पूंजीपतियों को सौंपने यानी लुटाने के लिए हम पर और जनता पर थोपी है. आदिवासियों को विस्थापित किए बगैर, हमारी पार्टी का सफाए किए बगैर संसाधनों की लूट संभव नहीं है.

१०. यह युद्ध हमारी जनताना सरकारों जो गरीब, उत्पीड़ित जनता के लिए आशा का किरण बनी हुई हैं, का सफाया करने के लिए चलाया जा रहा है.

११. यह युद्ध दरअसल भारत के संविधान का घोर उल्लंघन है. क्योंकि यह युद्ध 5वीं अनुसूची के इलाकों में लड़ा जा रहा है. पेसा कानून ग्रामसभाओं के अधिकारों की धज्जियां उड़ाया जा रहा है. अंतर्राष्ट्रीय न्याय सूत्रों, कानूनों, संयुक्त राष्ट्र संघ (युएनओ) के मूलवासी जनता से संबंधित चॉप्टर के नियमों का उल्लंघन है.

१२. हमारा प्रतिरोधी युद्ध जोकि जनयुद्ध है, न्यायपूर्ण है. यह बहुसंख्य जनता के फायदे के लिए है. तमाम उत्पीड़ित व शोषित जनता के हित में हमारी पार्टी काम कर रही है. हम सरकार के अन्यायपूर्ण युद्ध का मुकाबला कर रहे हैं. सिर्फ आदिवासी ही नहीं, व्यापक जनता के हित में, पर्यावरण विध्वंस को बचाने, संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाने हम इस युद्ध का प्रतिरोध कर रहे हैं. इसलिए हमारा प्रतिरोध न्यायपूर्ण है. जनताना सरकारों को बचाने और मजबूत करने, जल–जंगल–जमीन–अस्तित्व–अस्मिता–आत्मसम्मान को बचाने हमारी जनता, जन संगठन, पार्टी, पीएलजीए, जनताना सरकारें इस युद्ध के खिलाफ प्रतिरोध में हैं. आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसम्मान के लिए, क्रांति को सफल बनाने के लिए बलिदान देने तैयार हैं.

१३. जबकि पुलिस, अर्ध–सैनिक बल शोषकों जैसे अंबानी, अदानी, दमानी आदि के लिए अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं. अन्यायपूर्ण युद्ध इतिहास में कभी जीते नहीं. यदि जीतते भी हैं, तो वह अस्थायी ही होगी. अंतिम जीत जनता की ही होगी.

१४. हम इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ सहित देश, दुनिया के सभी मानवाधिकार संगठनों, प्रगतिशील, जनवादी बुद्धिजीवियों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, आदिवासी, गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों तथा अलग–अलग देशों की माओवादी पार्टियों व संगठनों, मजदूर वर्ग व मेहनतकश, मध्य वर्ग की जनता से अपील करते हैं कि वे भारत सरकार के पुलिस, अर्ध–सैनिक एवं सैन्य बलों द्वारा जनता पर किए जा रहे इस युद्ध के विरोध में, ड्रोनों द्वारा की जा रही हवाई बमबारी के खिलाफ, साथ ही इस युद्ध में थल सेना और वायु सेना को उतारने के विरोध में, कुल मिलाकर 'समाधान' के

प्रहार हमलों को तत्काल रोकने, बस्तर में सैन्यकरण एवं संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने की कवायद को बंद कराने आगे आवें. अपनी आवाज मजबूती से उठावें. आदिवासी जन जीवन को बाधित करने से मना करें. उन्हें वनोपजों के संग्रहण से रोकने, उनकी आजीविका को खत्म करने का विरोध करें.

१५. हम पत्रकार एवं मानवाधिकार साथियों, बुद्धिजीवियों से मांग करते हैं कि वे पामेड थाना, कैंपों में जाकर हालात का जायजा लें कि वहां किस बड़े और व्यापक स्तर पर हवाई हमलों की तैयारियां चल रही हैं. वहां बम–बारूद, ड्रोन ट्रकों में भरे हुए हैं. सारे आला अधिकारी वहीं डटे हुए हैं.

१६. इसलिए देशीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर इस हवाई हमले के खिलाफ व्यापक, जुझारू, संगठित जन आंदोलन का निर्माण करें. भारत में जनयुद्ध का समर्थन करें, उसकी हर संभव मदद करे.

**(विकल्प)**
**प्रवक्ता**
**दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी**
**भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)**